



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35) नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30—सितम्बर 5, 2008 (भाद्रपद 8, 1930)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 2008—SEPTEMBER 5, 2008 (BHADRA 8, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1049	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकारणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपरिधियत भी शामिल है) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 वा खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	6177
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	793	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सांविधिक नियम और आदेश	513
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	11	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, विचारक और भालोक्यापारीक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	6177
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1277	भाग III—खण्ड-2—पैटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पैटेंटें और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	8391
भाग II—खण्ड-1—जाधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिकारियों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक नियमों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	213
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रकर समितियों के विल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपरिधियत आदि भी शामिल हैं	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के अंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*	(1049)	*

*आकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1049	than the Administration of Union Territories).....*	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	793	PART II—SECTION 3—Sub-Section (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	11	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1277	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government	6177
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	513
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	8391
PART II—SECTION 3—Sub-Section (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	213
PART II—SECTION 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विभाग मंत्रालय
(उच्चतम शिक्षा विभाग)
वर्ष दिल्ली, दिवांक 20 अप्रैल, 2008

सं.एफ. सं. 1-1/2005-यू. 1ए/846

जबकि, केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (2007 का नं. 5) जिसे अग्ने सी.ई.आई. अधिनियम कहा गया है) केवल सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को दाखिले में आरक्षण उपलब्ध कराता है;

और जबकि, सी.ई.आई. अधिनियम अन्य पिछड़ा वर्ग को उन नागरिकों के वर्गों में परिभाषित करता है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं और ऐसा केवल सरकार ने निर्धारित किया है।

और जबकि, भारत सरकार ने पहचान की है कि सकल असमानताओं द्वारा विलित हमारे समाज में सामाजिक व्याय के उद्देश्य की शीघ्र उपलब्धि अविवार्य है, जैसा कि संविधान में उल्लेख किया गया है और इस प्रयोजन के एक माप के रूप में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग और मण्डल आयोग स्थापित किया है;

और जबकि, कथित मण्डल आयोग के विकाशर्थ विषयों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मानदण्डों का विर्धारण करवा और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की तरक्की के लिए उधाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना और विद्युक्तियों में आरक्षण नेतृ प्रावधान बनाने की व्यावहारिकता की अव्याधि जांच करना अथवा पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में पदों में आरक्षण जिव्हें संघ अथवा अन्य राज्य के मामलों में जब सेवाओं और पदों में पर्याप्त प्रतिविधित नहीं मिलता;

और जबकि, सरकार सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो लाभ देगी, जिसमें समग्र रूप से राज्य एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अंतर्गत पदों एवं रिक्तियों पर आरक्षण के साथ-साथ शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण सहित सामाजिक व्याय एवं सामाजिक समानता के विभिन्न उपाय शामिल हैं; उससे संबंधित आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है

और इसके बाद इस निर्णय पर घटुर्ही है कि शुरू में ऐसे वर्गों को संघ सेवाओं और उसके सार्वजनिक उपकरणों में कलिपय छूट दी जावी चाहिए:

और जबकि, इसलिए भारत सरकार के अंतर्गत स्थिविल पर्सों द्वारा रोताओं में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने और यह कि प्रथम चरण में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में वे जातियां एवं समुदाय शामिल होंगे जिनके नाम आयोग द्वारा तैयार की गई राज्य-वार सूची के साथ-साथ सरकारों की सूचियों, दोनों में सामाज्य रूप से उपलब्ध होंगे, के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) ने अपने दिनांक 13.8.1990 के कार्यालय घापन संख्या 36012/31/90- स्थापना (एस.सी.टी.) के द्वारा आदेश दिया था;

और जबकि, उपरोक्त कार्यालय घापन के अनुसारण में और मण्डल मामले में (इंदिया साहनी एवं अन्य बदाम भारत दौध एवं अन्य) उच्चतम व्यायालय ने दिनांक 15.11.1992 के विर्णव पर विचार करते हुए जिसमें व्यायालय ने उपरोक्त कार्यालय घापन और उपरोक्त कार्यालय घापन में उत्तिलिङ्गित समाजता के सिद्धांत जिसमें यह कहा गया कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप के पिछड़े वर्ग में वे जातियां एवं समुदाय शामिल होंगे जो मण्डल आयोग की रिपोर्ट की राज्य-वार सूची के साथ-साथ राज्य सरकारों की सूची दोनों में सामाज्य रूप से उपलब्ध हों;

और जबकि, मण्डल आयोग की रिपोर्ट एवं सिफारिशों और उपर उत्तिलिङ्गित कार्यालय घापन से यह स्पष्ट है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का अभिनिर्धारण एवं सूचीबद्ध किया जाना संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 16 (4) के तहत अविवार्य अदुखेदों सहित सभी प्रयोजनों के अनुच्छेदों और अन्य सभी सामाजिक व्याय संबंधी उपायों, जो कि सामाजिक असमानता सहित समानता एवं असमानता उभयूलन करने संबंधी संवैधानिक अध्यावेश से प्राप्त होता है, के लिए था; और यह कि भारत सरकार का हमेशा से यही उद्देश्य था, और यह कि उस समय कि गोजूदा परिवर्याति एवं संदर्भ के अनुसार अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण को केवल एक शुरूआती कदम (आरम्भतः) के रूप में लिया गया था, और इसे गलत नहीं समझा अथवा इसकी गलत व्याख्या नहीं की जावी चाहिए कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची केवल अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्यार्थी थी;

और जबकि, न तो भारत सरकार अथवा सरकारों के यहां यह प्रचलन है और न ही यह व्यावहारिक है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग/अन्य दिछड़ा वर्ग अथवा सामाजिक व्याय की आवश्यकता वाले किसी अन्य को प्रत्येक उद्देश्य हेतु पृथक रूप से अभिनिर्धारण एवं सूचीबद्ध किया जाए, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति गांमले में भी अभी तक यही सिद्धांत प्रचलित रहा है, और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के मानले में भी राज्य सूची से संबंधित यही विधि है जैसा कि उपर उत्तिलिङ्गित उच्चतम व्यायालय के निर्णय में दोष किया गया है जिसमें विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ावर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग, की राज्य सूचियां अनुच्छेद 16 (4) एवं 15 (4) दोनों ही उद्देश्यों के लिए तैयार की गई थीं, और भारतीय सामाजिक व्यवार्थ यह है कि प्रामाणिक रूप से सामाजिक रूप से प्रत्येक पिछड़ा वर्ग

शैक्षिक रूप से पिछ़ा वर्ग भी है और उक्त उत्तिलित विर्णव में उच्चतम व्यायालय ने उत्तेज्ज्ञ किया है कि भारतीय संदर्भ में सामाजिक पिछ़ेपन से शैक्षिक पिछ़ापन बढ़ता है;

और जबकि, प्रत्येक उद्देश्य हेतु प्रत्येक बार पृथक रूप से सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछ़े वर्ग का अभिनिर्धारण एवं सूचीबद्ध किए जाने से कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है बल्कि समय बर्बाद होता है;

और जबकि, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछ़े वर्ग/अन्य पिछ़ा वर्ग की प्रथम केन्द्रीय सूची को अधिसूचित करने संबंधी कल्याण मंत्रालय की दिनांक 10.09.1993 की संकल्प संख्या 12011/68/93 बी.सी.सी. (सी) में सख्तारी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का उद्देश्य का उत्तेज्ज्ञ करने का आशय यह बही था कि सामाजिक एवं शैक्षिक स्प से पिछ़े वर्ग/अन्य पिछ़े वर्ग का अभिनिर्धारण एवं सूचीबद्ध किया जाना केवल अनुच्छेद 16 (4) के लिए या बहिक वास्तव में अनुच्छेद 13 (4) के साथ-साथ अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्यों को सम्मिलित करते हुए सभी उद्देश्यों के लिए था जैसा कि इपर वर्णित किया गया है और समय-समय पर जारी की गई एस.ई.बी.सी./ओ.बी.सी. की केन्द्रीय सूचियों में अधिसूचित अनुवर्ती संकल्पों की स्थिति समान है, और सामान्य सूचीकरण और एन.सी.बी.सी. दोनों के आधार पर एन.सी.बी.सी. अधिनियम, 1993 की धारा 2 (ग) में सूचियों की परिभाषा के संबंध में भी यही स्थिति है (1993 की संख्या 27);

और जहाँ, केवल सरकार यो यह संतुष्टि है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछ़े वर्ग/अन्य पिछ़े वर्ग की केन्द्रीय सूचियाँ पूर्ण सावधानी से तैयार की गई हैं;

और आगे जहाँ, सामाजिक, और शैक्षिक रूप से पिछ़े वर्ग/अन्य पिछ़े वर्ग की केन्द्रीय (सामान्य) सूचियों के तैयार करने के लिए संदर्भित विभिन्न गज्जों की सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछ़े वर्ग/अन्य पिछ़े वर्ग की सूचियाँ रोजगार के लिए आरक्षण के लाभ को विस्तार देने के साथ-साथ विकास की अन्य कार्रवाईयों जैसे शैक्षिक संस्थानों में दाखिला तथा अत्रवृत्तियों आदि के लिए सज्जों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही थी और लाई जा रही है;

और जहाँ उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि सी.ई.आई. अधिनियम में संदर्भित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछ़े वर्ग/अन्य पिछ़े वर्ग को वर्तमान में कार्यान्वयित प्रत्येक उद्देश्य के लिए विशिष्ट किए जा चुके हैं तथा सी.ई.आई. अधिनियम के उद्देश्यों सहित अतिष्ठ नै समय-समय पर शुल किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा।

और जहाँ, एस.सी.बी.सी. की सलाह समय-समय पर संपादित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछ़े वर्ग/अन्य पिछ़े वर्ग की केन्द्रीय सूचियाँ, जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं जिसमें जन नीति निर्णयों के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछ़े वर्ग/अन्य पिछ़े वर्ग सम्मिलित हैं ताथ ही केवल सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए विद्युतियों अथवा पदों के आवक्षण के उद्देश्यों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के

अन्वर्गत किसी पिछड़े वर्गों के वाग्दिकों के पक्ष में, साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में अनुच्छेद 15 के रूप (4) के अन्वर्गत दिए गए शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के उद्देश्य के लिए जो कि उपरोक्त उत्तिलिक्षित राज्य सूची के समान रूप हैं और अनुच्छेद 15 के धारा (4) के तहत प्रदान किया गया है और ये छात्रवृत्ति प्रदान करने, अंत्रावास सुविधाएँ प्रदान करने, पिछड़े वर्ग के वाग्दिकों हेतु कोचिंग प्रदान करने जैसी योजनाओं सहित केन्द्रीय सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं में पहले से ही लागू किए गए हैं एवं लागू किए जा रहे हैं और समय-समय पर, जहाँ भी अपेक्षित होगा, और अधिक इस तरह की विकास योजनाएँ लागू किए जाएंगी।

इसलिए अब भारत सरकार, रपब्लीकरण के द्वारा पुनः पुष्टि करती है कि ऊपर उत्तिलिक्षित सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची सभी उद्देश्य हेतु है और हमेशा से रही है, जिसमें शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण शामिल है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और एतद्वारा कल्याण/सामाजिक व्याप्ति एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य-समय से राज्य-वार अधिसूचित सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की केन्द्रीय सूची को, रिट आचिका (संख्या 265) और अव्य संबंधित रिट आचिका भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.04.2008 के निदेशों के अनुसरण में सामाजिक रूप से उच्चतम व्यक्ति/वर्ग (जो सारांश रूप से “कीमीलेयर” कहे जाते हैं) को अव्य पिछड़ा वर्ग में शामिल न करने के संबंध में कार्रिक, लोक शिकायत और पैशन मंत्रालय (कार्रिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993 और उसके संशोधन दिनांक 9 मार्च, 2004 के ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना (रिस) तथा उक्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले संशोधन को केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2006 में वर्णित केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण के कार्यान्वयन के उद्देश्यार्थ स्वीकृत और अधिसूचित करती है।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य राज्यवार्गों, संघ राज्य प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों शिक्षा के स्तर के अनुरक्षण या विर्धारण हेतु बनाए गए सांविधिक विकायों एवं केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 के नियंत्रण में आके वाली सभी केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं (२००७ का लं ० ५) को भेजी जाए।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

**Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)**

New Delhi, the 20th April 2008

No. F.1-1/2005 – U.1 A/846

Whereas, the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 [No.5 of 2007] (hereinafter referred to as the ‘CEI Act’) provides for the reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Castes (SC), the Scheduled Tribes (ST) and the Other Backward Classes (OBC) of citizens to Central Educational Institutions established, maintained or aided by the Central Government.

And whereas, the CEI Act defines the “Other Backward Classes” as the class or classes of citizens who are socially and educationally backward, and are so determined by the Central Government;

And whereas, the Government of India had, recognizing that in our society marked by gross inequalities, early achievement of the objective of social justice as enshrined in the Constitution is a must, and established the Second Backward Classes Commission or the Mandal Commission as a measure pursuant to this purpose;

And whereas, the terms of the reference of the said Mandal Commission included the determination of the criteria for defining the socially and educationally backward classes (SEBC) and recommendation of steps to be taken for the advancement of the socially and educationally backward classes of citizens so identified and examination of the desirability or otherwise of making provision for the reservation of appointments or posts in favour of such backward classes of citizens which are not adequately represented in public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State;

And whereas, the Government carefully considered the Report and the recommendations of the Commission regarding the benefits that shall be extended to the socially and educationally backward classes, which comprehensively included various measures of social justice and social equalisation, including reservation in posts and vacancies under the State and public sector undertakings as well as reservation in educational institutions and, thereafter, came to the view that at the outset certain weightage has to be provided to such classes in the services of the Union and its Public Undertakings;

And whereas, therefore, orders were passed in its O.M. No. 36012/31/90-Estt. (SCT) dated 13.8.1990 of the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training) providing reservation of 27% in civil posts and services under the Government of India for socially and educationally backward classes, and that the SEBC would comprise in the first Phase, the castes and communities which are common to both the State-wise lists prepared by the Commission and the State Governments' lists;

And whereas, pursuant to the aforesaid O.M. and considering the judgment of the Supreme Court dated 15.11.1992 in its Mandal case (Indra Sawhney and Others vs. Union of India and Others) which upheld the aforesaid O.M. and the principle of commonality laid down in the aforesaid O.M. whereby the SEBC would comprise the castes and communities which are common to both the State-wise lists in the Report of the Mandal Commission and the State Governments' lists;

And whereas, it is clear from the Report and recommendations of the Mandal Commission and from the O.M. referred to above that the identification and listing of SEBC was for all purposes, of Articles including those under Articles 15(4) 16(4) of the Constitution and purposes of all other social justice measures which emerge from the Constitutional mandate of equality as well as the removal of inequality, including social inequality; and that this was always the intention of the Government of India, and it was only as an initial step ("at the outset"), in the situation and context then existing, that reservation under Article 16(4) was taken up, and this should not be misconstrued or

misinterpreted to mean that the Central Lists of SEBCs were intended for the purpose of only Article 16(4);

And whereas, it is not the practice of the Government of India or the State Governments, nor is it practical to identify and list SEBC/OBC or any other category in need of social justice for each purpose separately, and in the case of SC and ST also such has been the principle and practice all along, and in the case of SEBC this is the position in respect of State Lists as noted by the aforesaid Supreme Court judgment which specifically mentions that the State lists of SEBC/OBC were prepared both for the purposes of Article 16(4) as well as 15(4), and in the Indian social reality every genuine socially backward class is also an educationally backward class and it has been pointed out by the Supreme Court in the aforesaid judgment that in the Indian Context social backwardness leads to educational backwardness;

And whereas, no public purpose is served by identifying and listing SEBC for each purpose each time separately thereby losing time;

And whereas, the mention of the purpose of reservation in Government posts and services in the Resolution of the Ministry of Welfare No. 12011/68/93-BCC (C) dated 10.9.1993 notifying the first Central list of SEBC/OBC was not intended to mean that the identification and listing of SEBC/OBC was only for the purpose of Article 16(4) and was in fact for all purposes including for the purposes of Article 16(4) as well as Article 15(4) of the Constitution of India as elucidated above and the same is the position with the subsequent resolutions notifying Central list of SEBC/OBC issued from time to time, both on the basis of common listing and on the basis of Advices of the National Commission for Backward Classes (NCBC), and this is also the position in respect of the definition of Lists in Section 2 (c) of the NCBC Act of 1993 (No. 27 of 1993);

And whereas, the Central Government is satisfied that the Central Lists of the SEBC/OBCs, was prepared with due care;

And further whereas, the lists of SEBCs/OBCs of different States referred to for arriving at the Central (Common) Lists of SEBCs/OBCs were and are being used by States for extending the benefit of reservation for employment as well as for other measures of advancement such as admission to educational institutions and scholarships and so on;

And whereas, it is clear from the above that the SEBC/OBC referred to in the CEI Act have already been determined for each and every purpose currently in operation as well as those that may be undertaken from time to time in future, including for the purposes of the CEI Act;

And whereas, the Central Lists of SEBCs/OBCs, as modified from time to time on the advice of NCBC adequately reflect the various classes of population comprising the SEBC/OBC for the purpose of public policy decisions as to their welfare by the Central Government for the purposes of reservation of appointments or posts in favour of any backward classes of citizens under clause (4) of Article 16 of the Constitution of India, as well as for the purpose of advancement of socially and educationally backward classes as provided under clause (4) of Article 15 thereof in several States which have similar State Lists as mentioned above, as provided under clause (4) of Article 15 thereof and have already been and are being applied to various development schemes of the Central Government including the grant of scholarships, hostel facilities, coaching for the backward classes of citizens and more such developmental schemes will be taken up from time to time as required;

Now therefore, the Government of India, by way of clarification, reconfirms that the above mentioned Central Lists of SEBCs/OBCs are and have always been for all purposes including reservation in admission to educational institutions as elucidated above, and hereby notifies and adopts the Central Lists of SEBCs/OBCs notified State-wise from time to time by the Ministry of Welfare/Social Justice & Empowerment, subject to such modifications as may be made therein from time to time by that Ministry, excluding, in compliance with the directions of the Supreme Court of India dated

10.4.2008 in W.P (Civil) No. 265 and other related Writ Petitions, the Socially Advanced Persons/sections (commonly referred to as the “creamy layer”) in accordance with O.M. No. 36012/22/93-Estt.[SCT], dated 8.9.1993 of the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training) as amended by O.M. No. 36033/3/2004 – Estt. (Res) dated 9th March, 2004 and as may be modified by that Ministry from time to time, as applicable for the purposes of implementing reservation in admission to Central Educational Institutions as defined in the CEI Act 2006.

For and On Behalf of the President of India,

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all State Governments, Union Territory Administrations, Ministries/ Departments of the Government of India, Statutory Bodies responsible for the maintenance or determination of standards of education, and all central educational institutions under the purview of the Central Educational Institutions (Reservation in Admissions) Act, 2006 [No.5 of 2007].

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

